

## वडिफॉल टैक्स

वैश्विक मंदी की आशंका के बीच **कच्चे तेल** की कीमतों में कमी के साथ भारत सरकार ने **डीज़ल एवं विमानन टरबाइन ईंधन (Aviation Turbine Fuel-ATF)** पर हाल ही में लगाए गए **उपकरणों और शुल्कों** में कटौती की है तथा **पेट्रोल के नरियात पर उपकर हटा दिया है**।

### करों में कटौती:

- **वडिफॉल टैक्स:**
  - वडिफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए **अचानक बड़े मुनाफे पर लगाया गया उच्च कर दर है**।
- **करों में कमी:**
  - **पेट्रोल के नरियात पर 6 रुपए प्रति लीटर के बराबर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क हटा दिया गया है**।
  - **डीज़ल नरियात पर शुल्क पहले के 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 11 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है**।
  - **घरेलू रफाइनेरियों को अंतरराष्ट्रीय मूल्य के बराबर पर बेचे जाने वाले घरेलू कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (या वडिफॉल टैक्स) के माध्यम से उपकर को 23,250 रुपए प्रति टन से घटाकर 17,000 रुपए प्रति टन कर दिया गया है**।
  - **ATF पर नरियात शुल्क को 2 रुपए घटाकर 4 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है**।

### सरकार द्वारा बढ़ाई गई ड्यूटी:

- सरकार ने 1 जुलाई, 2022 को देश में ईंधन की कमी के मुद्दे को हल करने के लिये **पेट्रोल और डीज़ल** के नरियात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया।
- जून 2022 से देश भर के ईंधन पंपों द्वारा ईंधन की कमी की शिकायत की जा रही थी जिसके कारण उन्हें बंद कर दिया गया है।
  - ईंधन की कमी के परिणामस्वरूप सरकार ने शुल्क बढ़ा दिया।
    - इस कदम ने देश में पर्याप्त ईंधन उपलब्ध होने के प्रति आश्वस्त किया है और सरकार ने तेल वपिणन कंपनियों से कहा कि वे ईंधन पंपों को खुला रखें।

### वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें:

- वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई थी और घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों को अप्रत्याशित लाभ हो रहा था।
  - नज्दी तेल वपिणन कंपनियों अधिक लाभ के लिये बाहरी देशों में पेट्रोल और डीज़ल का नरियात कर रही थीं।
- खुदरा दुकानों पर ईंधन की कमी इसलिये उत्पन्न हुई थी क्योंकि तेल वपिणन कंपनियों नुकसान पर माल बेचने को तैयार नहीं थीं क्योंकि कच्चे तेल में बढ़ोतरी और रुपए में **गरिबट** के बावजूद कीमतों में वृद्धि नहीं हुई थी।
  - इन दो कारणों से तेल वपिणन कंपनियों को डीज़ल पर 20-25 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 10-15 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हुआ था।
- पछिले पखवाड़े में अमेरिकी और समग्र वैश्विक मंदी के कारण अंतर-महाद्वीपीय वनिमिय पर ब्रेंट बेंचमार्क अनुबंध में 12% से अधिक की गरिबट आई है, जिसने सरकार द्वारा लगाए गए ड्यूटी की समीक्षा करने के लिये प्रेरित किया है।

### यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न:

**प्रश्न.** संविधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइये। क्या आप समझते हैं कि यह "करों के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने में वस्तुओं तथा सेवाओं के लिये साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में" काफी प्रभावकारी है? (2017, मुख्य परीक्षा)

### स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

